

टेस्ट क्रिकेट खेल का शिखर बना हुआ है और मैं प्रशंसकों के लिए इसके आकर्षण को बढ़ाते हुए इसके कद को बनाए रखने के लिए समर्पित हूं। साथ ही, महिला क्रिकेट हमारी विकास रणनीति का आधार होगा क्योंकि हम इस खेल को नए क्षितिज पर ले जाएंगे।

-जय शाह



हिंदी दैनिक, जन एक्सप्रेस

@janexpressnews

janexpresslive

www.janexpresslive.com/epaper

janexpresslive

लखनऊ, मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024

06

जन एक्सप्रेस



सम्पादकीय

नीतिगत क्रियान्वयन, भारत और सहकारिता आंदोलन

समितियों को एक-दूसरे के तुलनात्मक लाभों से लाभान्वित करने की सुविधा प्रदान कर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस पहल में वित्तीय पक्ष से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु- सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के मौजूदा बैंक खातों को विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में समर्पित करना और उन्हें एक केंद्रीकृत जिला/राज्य सहकारी के तहत रखना होगा, जिससे सहकारी प्रणाली के संसाधन प्रणाली के भीतर ही बने रहेंगे।भविष्य में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।

श्री के.बी.साहू आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समावेशी विकास रणनीति सहकार से समृद्धि के देश में अब तक काफी कारगर नतीजे सामने आए हैं। स्वतंत्रता से पहले के दौर में अगर हम भारत में सहकारिता आंदोलन की उत्पत्ति को देखें तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत किसानों की गरीबी कम करने की चुनौती से हुई थी, जिसका मुख्य कारण बार-बार पड़ने वाला सूखा और साहूकारों की सूदखोरी प्रवृत्ति था। एनएफआईएस, 2021-22 के अनुसार यह काफी प्रसवता का विषय है कि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के माध्यम से केंद्र सरकार की निरंतर और लक्षित वित्तीय समावेशी पहलों के कारण, ग्रामीण परिवारों को साहूकारों और जमींदारों पर निर्भरता अब घटकर मात्र 4.2 प्रतिशत रह गई है।देश में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली प्रारंभिक शक्तियां भले ही अब कमजोर पड़ रही हों, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस समय कई नई और जटिल उभरती चुनौतियां हैं, जिनके लिए सहकारी आंदोलन को नई दिशा और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो सपना देखा है, उसी के अनुरूप देश 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।इन नई चुनौतियों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर एक कुशल ग्रामीण आयुर्वि श्रृंखला हासिल करना, स्थायी आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति को कम करना, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि उत्पादकता तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले प्रयासों को बढ़ाना और डिजिटल क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाना शामिल है। सहकारी संस्थाएं अपने मजबूत स्थानीय ज्ञान, पूर्व की घटनाओं से अनुभव हासिल कर भविष्य की नई योजनाएं, संपर्क कार्यक्रम बनाने तथा इन्हें मजबूत करने की क्षमता और नए कारोबारी माहौल के अनुरूप ढलने के कारण इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती हैं। सहकारी संस्थाओं के लिए मददगार नीतियां बनाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामाजिक विकास में सहकारी समितियों पर रिपोर्ट (जुलाई 2023) से जानकारी प्राप्त करना उपयोगी हो सकता है, जो इस बात पर जोर देती है कि सहकारी समितियां बाजार संबंधी विफलताओं से निपटने, हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाकर सतत विकास को सहारा देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह रिपोर्ट सहकारी समितियों के लिए एक उद्यमी प्रक्रियागत दृष्टिकोण की सिफारिश करती है, जो एक स्थानीय माहौल में आपस में जुड़े हुए नेटवर्क के माध्यम से सभी हिस्सेदारों को जोड़ती है।भारत के सहकारी क्षेत्र में दुध और चीनी के क्षेत्रों में मिली अपार सफलता केवल एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व को ही प्रमाणित करती है। इसका एक और अन्य सफल उदाहरण भारत की सबसे पुरानी श्रमिक सहकारी संस्था- उतालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी का है, जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी है और इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रही है। यह वैकल्पिक उद्यमशीलता मॉडल का एक अनूठा उदाहरण है। यहां सहकारिता के दो विशिष्ट पहलुओं का उल्लेख करना आवश्यक है: पहला, सहकारी समितियों के बीच सहयोग का महत्व- जब उतालुंगल को एक सड़क परियोजना हेतु लिए गए भारी कर्ज की किराये चुकानी थीं, तो उसने 38 प्राथमिक सहकारी समितियों का एक संघ बनाया।

एक्सप्रेस स्वास्थ्य

एसिडिटी होने पर गुनगुना पानी पीना होता है फायदेमंद, मिलते हैं कई फायदे

एसिडिटी होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे लेट नाइट खाना खाना, स्पाइसी चीजों का सेवन अधिक मात्रा में करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लेना, दिन भर में बार-बार कॉफी या चाय पीना आदि। एसिडिटी की समस्या किसी को भी हो सकती है। कई बार प्यास नंद न लेना, लेट नाइट मॉचिंग करना और कुछ मेडिसिन लेने के कारण भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। यही नहीं, विशेषज्ञों की मानें, तो एसिडिटी की समस्या स्ट्रेस, स्मॉकिंग की वजह से भी होती है। जिन्हें अक्सर एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें सादा भोजन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, अपने सोने के पैटर्न में बदलाव करने तथा जल्दी भोजन करने को कहा जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि गुनगुना पानी पीने से भी एसिडिटी की समस्या दूर होती है। सवाल है, क्या वाकई गुनगुना पानी एसिडिटी से राहत दिलाते का काम करता है?

गुनगुना पानी पीने के कारण यह हमारे खाए हुए फूड आइस्टम को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इससे हमारी पाचन क्षमता को भोजन पचाने में आसानी होती है। विशेषज्ञ आगे बताते हैं, कई बार स्पाइसी या बासी खाना खाने की वजह से पेट में एसिड बन जाता है, जिससे एसिडिटी हो जाती है। गुनगुना पानी पीने से स्टम एसिड डाइन्यूट हो जाता है, जिससे एसिडिटी से आराम मिलने लगते हैं। यही नहीं, गुनगुना पानी पीने से पेट के टॉक्सिंस बाहर चले जाते हैं, जो पाचन क्षमता और पेट की समस्या को दूर करने में मददगार साबित होता है।

पाचन क्षमता में सुधार: जिन लोगों की पाचन क्षमता में दिक्कत होती है, उन्हें अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है।



गुनगुना पानी पीने से पाचन क्षमता में सुधार होता है, जिससे एसिडिटी की आशंका कम होती है। साथ ही, एसिडिटी हो तो वह भी दूर होती है। पेट की जलन दूर होती है। जब आप पेट में एसिड बनने पर लगातार गुनगुना पानी पीते हैं, तो इससे एसिड डाइन्यूट होने लगता है। ऐसे में पेट की जलन में कमी आती है। कई बार एसिडिटी होने पर एसोफेगस यानी फूड पाइप में हो रही जलन भी दूर हो जाती है।

टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं: आपने अक्सर विशेषज्ञों को कहते सुना होगा कि आप जितनी ज्यादा मात्रा में पानी पिएंगे, उतने ही बांडे के टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं। इससे किडनी, लिवर और हार्ट भी अच्छे तरह से काम करते हैं, जिससे ओवर ऑल हेल्थ में सुधार होता है। इसी तरह, जब एसिडिटी हो, तो गुनगुना पानी पीने से पेट के एसिड को भी बाहर निकलने में मदद मिलती है। इससे पेट की एसिडिटी की समस्या भी कम होने लगती है।

एसिडिटी दूर करने के लिए किस तरह गुनगुना पानी पिएं: यह सही है कि गुनगुना पानी पीने से एसिडिटी से राहत मिलती है और पाचन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। लेकिन, इसे सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए।

विचार एक्सप्रेस



बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को शुभेंदु की...

बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को लेकर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनके... » पृष्ठ 12 पर...

एक्सप्रेस आलेख

जिन्ना की 11 सितंबर, 1948 को मौत के साथ ही मंडल की वहां पर दुर्गति चालू हो गई थी। उनकी हर सलाह को नामंजूर कर दिया जाता। नतीजा यह हुआ कि वे पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। ये 1951 के आसपास की बातें हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ नाइंसाफी होती है। इसलिए उनका पाकिस्तान में रहना मुमकिन नहीं होगा। मंडल उसके बाद कोलकत्ता आ गए। उनका 1968 में निधन हो गया। मंडल ने जो कहा था, वह अक्षरशः सही निकला। पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। इसी का नतीजा था कि जिन्ना का करीबी एक दलित हिन्दू मंत्री तक पाकिस्तान में नहीं रह सका।

पाक में क्यों बह रहा शिया मुसलमानों का खून



आर.के. सिन्हा

मंडल को जिन्ना ने अपनी कैबिनेट में विधि मंत्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा था कि इस्लामिक पाकिस्तान में सबके हक सुरक्षित हैं। पर हुआ इसके ठीक विपरीत। मंडल पाकिस्तान के पहले और शायद आखिरी हिन्दू मंत्री बने। वे वहां पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता थे।

मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस इस्लामिक देश पाकिस्तान को बनवाया था, वहां मुसलमान ही अब मुसलमानों की जान के दुश्मन हो गये हैं। वहां सुन्नी और शिया समुदायों के बीच हुए हालिया संघर्ष में 100 से ज्यादा लोगों का खून बहा। हिंसा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम जिले में हुई। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी में शिया मुस्लिम लगभग 15 प्रतिशत ही हैं। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का हालिया संघर्ष जटिल है, जिसके जड़ें सदियों पुरानी धार्मिक और राजनीतिक विभाजन के इतिहास पर टिकी हैं। वैसे तो कुछ कट्टरपंथी समूह तो दोनों पक्षों में ही मौजूद हैं जो हिंसा का इस्तेमाल करके ही अपने धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ये समूह साम्प्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और हिंसा को सही ठहराते हैं। पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय कतई शिया मुसलमानों को पसंद नहीं करते। इससे साफ है कि इस्लाम अपने मानने वालों को भी नहीं जोड़ता। हालांकि बातें बहुत होती हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं। लेकिन , ये अपनी इस बात को तो स्वयं ही बार-बार गलत साबित करते रहते हैं। पाकिस्तान में शिया मस्जिदों में धमाके और विस्फोट होना भी आम बात हो चुकी है। पेशावर में मई, 2022 में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुए दिल दहलाने वाले आत्मघाती बम विस्फोट में लगभग 60 से अधिक शिया नमाजी मारे गए थे। हमलावरों ने निशाना बनाया था शिया मुसलमानों और उनकी इबादतगाह को। यह भी याद रखा जाए कि एक इस्लामिक मुल्क में ही शिया मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। वे हर वक डर-भय के साए में जीने को मजबूर बने रहते हैं। यह हाल उस पाकिस्तान का है जो मुसलमानों के वतन के रूप में बना था। पेशावर की शिया मस्जिद में हुआ हमला कोई अपने आप में पहली बार नहीं हुआ था। वहां पर शिया मुसलमानों पर लगातार जुल्मों-सितम होते रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार प्रतिबंधित संगठन शियाओं के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन भी करते हैं। इस तरह के ज्यादातर प्रदर्शन लाहौर, क्रेटा, पेशावर वगैरह शहरों में देखने को मिलते हैं। वहां पर शिया मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने वाला साहित्य भी हर जगह आसानी से वहाँ पर आम लोगों को आसानी से उपलब्ध है।



हालांकि 11 अगस्त,1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भाषण में यह कहा था कि पाकिस्तान में सभी धर्मों के मानने वालों को अपने धार्मिक स्थानों में जाने की अनुमति होगी। यानी पाकिस्तान के विश्व मानचित्र में आने से सिर्फ तीन दिन पहले। उन्होंने अपनी कैबिनेट में जोगिन्दर नाथ मंडल नाम के एक हिन्दू को शामिल भी किया था।

है। तालिबान और इसी तरह के अन्य अतिवादी समूहों के विचारों का प्रभाव पाकिस्तान में है, जो साम्प्रदायिक संघर्षों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए शिया-सुन्नी संघर्ष का उपयोग आम तौर पर करते हैं। पाकिस्तान में कुछ सियासी नेता साम्प्रदायिक तनाव को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे मतदाताओं को लुभाने के लिए और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काते हैं। बेशक, पाकिस्तान सरकार की सुन्नी परस्त नीति के कारण साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में नाकामी, या यहां तक कि कुछ मामलों में इसमें सहयोग करने से, इस समस्या को और बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान में कुछ सुन्नी जिन्ना को भी शिया बताते हैं। कौन जाने की एक बार जिन्ना शिया साबित कर दिए गए तो उनकी विरासत को भी बिना कुछ जाने समझे ही पाकिस्तान में धूल में मिला दिया जायेगा। पाकिस्तान में

एक्सप्रेस ज्ञान

जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है, जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है



- कृष्णेंद्र राय

एक्सप्रेस विशेष

एमपी उपचुनाव का परिणाम और मोहन सरकार का कामकाज

एमपी की मोहन यादव सरकार को 13 दिसंबर को सालभर पूर्ण हो जाएगा। बीते वर्ष की इसी तारीख को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी में उज्जैन के विधायक मोहन यादव को प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा था। अब जबकि मोहन यादव की सरकार को सालभर हुआ जाता है। यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार कैसा काम कर रही है। इस लिहाज से प्रदेश की भाजपा सरकार के कामकाज की समीक्षा होना चाहिए।



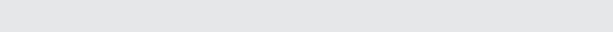
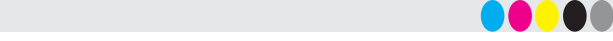
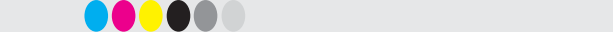
- नरेंद्र तिवारी

प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को एक वर्ष का समय होने जा रहा है। एक सरकार के लिए सालभर का समय यूं तो कम है। उपचुनाव में प्राप्त मिलीजुली सफलता को सरकार के मुखिया के मूल्यांकन का आधार माना जा सकता है।

विजयपुर में भाजपा की हार और बुधनी में जीत के अंतर का कम होने का अर्थ सरकार के कामकाज से नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। 2023 में मध्यप्रदेश में प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के मुखिया के रूप में शिवराज सिंह चौहान को बदलकर नए चेहरे के रूप में मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना था। भाजपा का यह प्रयोग प्रदेश की जनता को भी अर्चभित करने वाला माना गया था।

कारखाने में ऐसे नेताओं का निर्माण बंद हो गया जो अपनी ही सरकार की आलोचना कर दे या जो विपक्ष में रहते हुए भी सरकार के कामकाज की तारीफ कर सके। कुलमिलाकर राज्य सरकारों के कामकाज की समीक्षा का हाल टीवी पर चलती पार्टी प्रवक्ताओं की अंतहीन और बेनतीजा बहस की तरह ही दिखाई पड़ता है। सही मायने में सरकार के कामकाज की असली समीक्षक राज्य की जनता ही होती है। जनता जो चुनाव के माध्यम से अपने मताधिकार को ताकत से राज्य सरकार के कामकाज पर अपनी मोहर लगाती है। महाराष्ट्र में भाजपानीत महायुक्ति की प्रचंड विजयी राज्य की सत्ताधारी सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कामकाज पर जनता की मोहर है। झारखंड राज्य में जेमत सोरेन की वापसी राज्य की जनता का मुख्यमंत्री के कामकाज को आशीर्वाद प्रदान करना ही माना जाएगा। सरकार के कामकाज की असली समीक्षक प्रदेश की जनता है। इस लिहाज से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कामकाज की समीक्षा को एमपी के दो

को हुए उपचुनाव में यहां भाजपा के रमाकांत भार्गव और कांऐस के राजकुमार पटेल के मध्य मुकाबले में भाजपा ने इस सीट पर 13848 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। यह अंतर विधानसभा चुनाव 2023 के मुकाबले काफी कम है। बुधनी से शिवराज चौहान ने एक लाख से अधिक मतों से विजय दर्ज की थी। उसके मुकाबले यह विजय बेहद कमजोर है। बुधनी में सरकार के कामकाज से प्रभावित और खुशी जाहिर करने वाले मतदाताओं को संख्या में कमी हुई है। उपचुनाव रथेपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में भी हुआ जहां का परिणाम प्रदेश की सरकार और मुखिया मोहन यादव के कामकाज से जनता की नाराजी व्यक्त करता प्रतीत हो रहा है। यहां हुए चुनाव में कांऐस से भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। कांऐस ने मुकेश मल्होत्रा पर दांव खेला था। रामनिवास रावत जो भाजपा की सरकार में वन मंत्री बना दिए गए थे। चुनावी रण में कांऐस उम्मीदवार से 7000 मतों से पराजित हो गए। आमतौर पर माना जाता है कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल के विजय रहने की संभावना बहुत अधिक रहती है। विजयपुर में भाजपा का पराजित होना सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यप्रणाली से क्षेत्र की नाराजी के तौर पर देखा जा रहा है।



गोवंश आश्रय केंद्र बिशुनापुर की गाउंड रिपोर्ट... गौशाला के अंदर नहीं मिला हरा चारा, अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक

जन एक्सप्रेस । बलरामपुर

जनपद बलरामपुर के विकासखंड सदर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिशुनापुर में स्थापित गोवंश आश्रय केंद्र पर जन एक्सप्रेस टीम ने पहुंचकर स्थानीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली, परंतु पशुओं को खाने के लिए हरे चारे की व्यवस्था दिखाई नहीं दी। बलरामपुर-गोंडा-बहराइच बाईपास पर कलेक्ट्रेट से महज 1 किलोमीटर दूरी पर स्थापित ग्राम पंचयत बिशुनापुर की गौशाला में पशुओं को ठंडक से बचाव हेतु बोरे की पल्ली लगाकर प्रयास किया गया है। गौशाला में रह रहे पशुओं को ठंडक से बचाने के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में गौशाला में गौशेणों के रहने वाले क्षेत्र को बोरे की पल्ली लगाकर इस कदर ढका गया है जिससे शीतलहर तथा ठंडी हवाओं का प्रभाव कम से कम हो। गौशाला में रह रहे गौवंशों को खाने के लिए भूसे की व्यवस्था की गई थी, परंतु हरा चारा कहीं दिखाई नहीं दिया। पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था दिखाई दी। गौशाला के अंदर



स्वच्छता व्यवस्था भी संतोषजनक दिखाई दी। ग्राम प्रधान नाजिर अहमद ने बताया कि गौशाला में पशुओं को ठंडक से बचाने के लिए बोरे की पल्ली लगाकर व्यवस्था की गई है। गौशाला का छजन भी सही स्थिति में है। पशुओं के खाने के लिए भूसा की व्यवस्था है, जबकि हरा चारा के लिए एक एकड़ चरी लगाया गया है, जिससे पशुओं को हरा चारा मिल रहा है। पीने के लिए पानी का पर्याप्त व्यवस्था की गई है। स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

–नाजिर अहमद, ग्राम प्रधान बिशुनापुर विकास खंड व जनपद बलरामपुर मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निर्देश दिया गया है कि गोवंशों को ठंड से बचाव हेतु गोआश्रय स्थलों में शीत लहर के प्रभाव को रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए त्रिपाल, बोरा, पराली, इत्यादि का प्रबन्ध समयमय कर लिया जाये। गोआश्रय स्थलों में निर्मित शेड को त्रिपाल एवं बोरे आदि से विधिवत

कवर करा दिया जाये, जिससे ठण्डी हवाओं से गोवंशों को सुरक्षित रखा जा सके। ठंड से बचाव हेतु जूट के बोरे के झूल का उपयोग किया जाये। आवश्यकता पड़ने पर जनपद स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध अनुपयोगी बोरे/टाट आदि को गोआश्रय स्थलों को उपलब्ध कराकर प्रयोग में लिया जाये। गोआश्रय स्थलों की समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित करायी जाये। गोआश्रय स्थलों में पानी, गोबर, गोमूत्र आदि की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाये।

अपर जिलाधिकारी ने उपनिबंधक कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

जन एक्सप्रेस । अम्बेडकरनगर

जनपद के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ० सदानन्द गुप्ता द्वारा कार्यालय उपनिबंधक टाण्डा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपनिबंधक सत्येन्द्र कुमार यादव, निबन्धन लिपिक राजेन्द्र प्रताप सिंह व शरीफुज्जमा, कम्प्यूटर ऑपरेटर विशाल तिवारी व परिचर फूलचन्द अपने-अपने कार्यों को करते पाए गये।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा बैनामा, मुआयना आदि के लिए उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ भी की गयी। पूछताछ के दौरान कार्यालय के प्रति कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुयी, सभी का कार्यालय के



प्रति सकारात्मक रूख रहा। अपरजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा उपनिबंधक टाण्डा को निर्देशित किया गया कि शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के साथ कार्यालय परिसर में पारदर्शी व्यवस्था के तहत कार्य किया जाय एवं

जनता के हित के प्रति अपने कार्यों को जिम्मेदारी से निर्वहन किया जाय। साथ ही आई०जी०आर०एस० या जनता दर्शन आदि से प्राप्त शिकायती प्रार्थनापत्र का समयमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाय।

डीएम ने किया ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण



जन एक्सप्रेस । बलरामपुर

जनपद बलरामपुर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया । जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी पवन अग्रवाल ने एवं एवं वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण करने के उपरांत सीसीटीवी कंट्रोल रूम में सभी कैमरों की सुचारू रूप से संचालन

का जायजा लिया। उन्होंने एक सप्ताह पूर्व के रिकॉर्डिंग का भी अवलोकन किया। उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था एवं अभिलेखों के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने अग्निशमन यंत्र का माँक परीक्षण कराकर क्रियाशीलता का जायजा लिया। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार, डीपीआरओ श्रेया उपाध्याय, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कासगंज में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, खेत में पड़ा मिला शव

जन एक्सप्रेस । कासगंज

कासगंज के थाना सोरोंजी क्षेत्र के गांव मौजमपुर में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेत में सुबह के समय लाश पड़ी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कासगंज के थाना सोरोंजी क्षेत्र के गांव मौजमपुर में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव गांव के बाहर एक खेत में पड़ा मिला है। उसके पास तमंचा भी पड़ा हुआ मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि पुलिस आत्महत्या के एंगल पर भी जांच कर रही है। परिजन ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। गांव मौजमपुर निवासी प्रमोद कुमार (50) पुत्र राजपाल का शव सोमवार की सुबह गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला। खेत पर काम करने गए ग्रामीणों ने जैसे ही शव देखा उन्होंने शोर मचाया। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीओ सिटी आंचल चौहान, थाना सोरोंजी प्रभारी जगदीश चंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पहले दोस्ती, फिर बनाए संबंध, बना डाला अश्लील वीडियो, अब मांग रहा पांच लाख

जन एक्सप्रेस । अलीगढ़

तलाकशुदा महिला की मुलाकात रोहित से हुई। इसके बाद दोनों साथ में ही रहने लगे। फिर शादी की बात करते हुए उसके संग शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि जब वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भ गिरवा दिया। अलीगढ़ के थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र की एक महिला ने फरीदाबाद निवासी युवक पर शादी के बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाने व वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाया है। इस मामले में एएसपी की आदेश पर पीड़िता ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला के थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा

कि वह तलाकशुदा है और बल्लभगढ़ में रहकर निजी कंपनी में नौकरी करती थी। जहां उसकी मुलाकात मल्लैना रोड, विजयनगर थाना, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा निवासी रोहित से हुई। इसके बाद दोनों साथ में ही रहने लगे। फिर शादी की बात करते हुए उसके संग शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि जब वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भ गिरवा दिया। 15 मई 2024 को आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद व हाईकोर्ट इलाहाबाद जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद दोनों महिला के गांव में आकर रहने लगे। इसी बीच 20 अगस्त 2024 को उसने कहा कि कुछ जरूरत है, मैं घर जा रहा हूं। इसी के साथ महिला का एटीएम व 10 हजार रुपये लेकर चला गया। 22 अगस्त

को महिला को अपने साथ बल्लभगढ़ ले गया। आरोप है कि यहां बंधक बनाकर कमरे में रखते हुए मारपीट की गई। महिला ने उसके परिवारीजनों से शिकायत की तो ऊट्टा उसे पीटा गया। आरोप है कि रोहित ने उसके एटीएम से साढ़े 11 हजार रुपये निकाले और अपने साथ अहमदाबाद ले गया। आरोप है कि वहां भी उससे गर्भ गिराने का दबाव बनाता रहा। जैसे- तैसे महिला ने अपने सहेली को पत्र करके जानकारी दी, तब जाकर पुलिस की मदद से उसे थाने पहुंचाया। वहां मुकदमा नहीं लिखा, बल्कि उसे फ्लाइंट से घर भेज दिया। अब रोहित द्वारा महिला को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में किया प्रदर्शन

अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा

जन एक्सप्रेस । बलरामपुर

जनपद बलरामपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बांग्ला देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बोरोध में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर मे प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी प्रदीप कुमार को सौंपा।

अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जगदंबा प्रसाद मिश्रा ने 2 दिसंबर को बताया कि बांग्लादेश इस्कॉन पुजारी की देश द्रोह के लिए गिरफ्तारी बांग्लादेश में हाल के महीनों में हिंदू अल्पसंख्यकों के



खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजनीतिक अस्थिरता और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद स्थिति और खराब हो गई है। मुस्लिम कट्टरपंथी समूहों द्वारा हिंदू घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के

मुताबिक, 27 जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। हिंदू नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जिससे समुदाय में गहरी नाराजगी है। हाल ही में 19 हिंदू नेताओं पर राष्ट्रध्वज अपमान के आरोप लगाए गए और

दो को गिरफ्तार किया गया। चिटगांव में हजारों हिंदुओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की। इस दौरान महिलाओं और बच्चों पर भी हमले बढ़े हैं। नोवाखली जैसे इलाकों में लूट और अपहरण की घटनाएं सामने

खेत में पड़ा मिला युवक का शव : पहले टेप से बांधे हाथ, फिर मुंह पर चिपकाया, गर्दन रेती, चेहरा जलाया

जन एक्सप्रेस । अलीगढ़

पुलिस शव की हालत देखकर हैरान रह गई। शव के दोनों हाथ कपड़े की टेप से बंधे हुये थे। शव का गला रेटा हुआ था। हत्यारे ने शव की पहचान छुपाने के लिए आस-पास पड़ी पॉलिथीन को चेहरे पर रखकर पूरी तरह से जला दिया। युवक का शव खेत में पड़ा मिला है। युवक के हाथ और मुंह को बांधा गया। उसकी गर्दन रेती और पहचान छिपाने के लिए चेहरे को जला दिया गया। थाना छर्पा के अतरीली रोड़ स्थित गुप्ता मोड़ के निकट हबीबपुर बंबा के पास खेत में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुंच गए। शव की शिनाख्त नहीं हुई है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लग गई है। 2 दिसंबर की सुबह लगभग 11 बजे खेत में शव पड़ा देख ग्रामीणों ने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना



पर सीओ छर्पा महेश कुमार एवं थाना कोतवाली निरीक्षक राजेश कुमार मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच करते हुए शव की शिनाख्त हेतु ग्रामीणों को बुलाकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं मिली। सूचना पर एसपीआरए मुकेश चन्द्र उत्तम, एएसपी अरीना नोमान, एसडीएम अतरीली साहिल कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस शव की हालत देखकर हैरान रह गई। शव के दोनों हाथ कपड़े की टेप से बंधे हुये थे। शव का गला रेटा हुआ था। हत्यारे ने शव की पहचान छुपाने के लिए आस-पास पड़ी पॉलिथीन को चेहरे पर रखकर पूरी तरह से जला दिया। जिससे शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि मृतक लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच में होगा। साथ ही युवक

ने गहरे हरे रंग का लॉअर, नीली और सफेद चेक की शर्ट पहन रखी है। उसके हाथ में कड़ा है और दोनों हाथों पर टैटू बना हुआ है। छर्पा कोतवाली पुलिस के अनुसार शव की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया के अलावा अलीगढ़ एवं जनपद के बाहर थानों से सम्पर्क किया जाएगा। साथ ही हत्या की घटना के खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटे व सर्विलांस टीम की मदद ली जायेगी।

आगरा कॉलेज में ऐसी छिड़ी प्राचार्य पद की रार

जन एक्सप्रेस । आगरा

आगरा कॉलेज में प्राचार्य पद की रार के चलते शैक्षणिक सत्र पटरी से उतर गया है। आलम ये है कि नियमित कक्षाएं तक नहीं लग पा रही हैं। ये विवाद डेढ़ साल से चल रहा है। आगरा कॉलेज में प्राचार्य पद की रार से शैक्षणिक सत्र पटरी से उतर गया है। शिक्षकों की गुटबाजी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्राचार्य पद के लिए करीब डेढ़ साल से विवाद चल रहा है। इससे कक्षाएं अनियमित हो गई हैं। आगरा कॉलेज में विवाद की वजह से शिक्षक भी दो गुटों में बंट गए हैं। सीधा असर पढ़ाई पर पड़ रहा है। शोध कार्य प्रभावित है। छात्रों का कहना है कि दोनों गुटों के शिक्षक अपने पक्ष के हित में बैठक व अन्य कार्य में समय अधिक बिता रहे हैं। रोस्टर से पढ़ाई नहीं हो रही है। कक्षाएं भी अनियमित हैं। प्रवेश कार्य पिछड़ गया है। विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष गौरव शर्मा का कहना है कि शिक्षकों में गुटबाजी है और वे छात्रों के बजाय प्राचार्य बनाने के लिए पूरी शक्ति खर्च कर रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

एनएसएस के नोडल अधिकारी को बेहतर प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित

■ छात्र पुलिस अनुभवाम्त्वक अधिगम स्वच्छता कार्यक्रम में मिला सम्मान
जन एक्सप्रेस । बलरामपुर

जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के एमएलके पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आलोक शक्ला को स्वच्छता अभियान में बेहतर प्रदर्शन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के एपी सेन ऑडिटोरियम हॉल में सोमवार को आयोजित सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार 2 नवंबर को माई भारत पोर्टल के माध्यम से प्रथम चरण के छात्र पुलिस अनुभवाम्त्वक अधिगम कार्यक्रम कार्यक्रम अधिकारी डॉ आलोक शक्ला ने नोडल अधिकारी के रूप में अपने दो स्वयं सेवकों के साथ



स्वयंसेवकों को सम्मानित करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के एपी सेन ऑडिटोरियम हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में एमएलके पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ आलोक शक्ला ने नोडल अधिकारी के रूप में अपने दो स्वयं सेवकों के साथ

सम्मान प्राप्त किया। बताते चलें कि के कार्यक्रम के शुभारम्भ हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम 02 दिसंबर, 2024 को 11:00 से 15:00 बजे तक एपी सेन सभागार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ मुख्य अतिथि एवं पुलिस

प्रमाण पत्र वितरण एवं द्वितीय चरण के कार्यक्रम के शुभारम्भ हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम 02 दिसंबर, 2024 को 11:00 से 15:00 बजे तक एपी सेन सभागार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ मुख्य अतिथि एवं पुलिस

महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे । इस अवसर पर आशीष गुप्ता पुलिस महानिदेशक रूल एंड मैनुएल्स उत्तर प्रदेश सरकार, देवरंजन वर्मा आईपीएस एसपी डीजीपी हैडक्वार्टर्स, मंजू सिंह राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी उच्चतर शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश राज्य, समरदीप सक्सेना रीजनल डायरेक्टर ऑफ एनएसएस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी मौजूद थे । राष्ट्रीय सेवा योजना कि इस उपलब्धि पर महाविद्यालय प्राचार्य प्रो० जे पी पाण्डेय, मुख्य नियंता प्रो० राधेवंद सिंह, प्रो० अरु के सिंह, पूर्व नियंता प्रो० पी के सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉ राजीव रंजन, लेफ्टिनेंट डॉ देवेन्द्र कुमार चौहान व डॉ अनामिका सिंह सहित तमाम प्राध्यापकों तथा शुभ चिंतकों ने बधाई दी है।

इंडिया&वर्ल्ड

12

‘संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार और विपक्ष साथ आए’

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है, वहीं उसका आरोप है कि सत्ता पक्ष की तरफ से उनकी मांगें न माने जाने के कारण संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल पा रही है। जिसकी वजह से संसद के महत्वपूर्ण छह दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। इसे लेकर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तमाम दलों के साथ एक बैठक भी की है। इस बैठक में टीडीपी के लवू श्री कृष्ण देवरायलू, कांग्रेस नेता गौरव गोगाई, डीएमके सांसद टी आर बाबू , एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के धर्मेन्द्र यादव, जेडी(यू) के दिलेश्वर कामैत, आरजेडी के अध्यक्ष कुशवाह, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत और सीपीआइ के राधाकृष्णन शामिल हुए। वहीं इस बैठक में दोनों पक्षों (सरकार और विपक्ष) में



लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर होगी चर्चा

13-14 दिसंबर को हम संविधान पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोकसभा में चर्चा होगी। सभी ने इसे स्वीकार किया है। 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। स्पीकर ने यह भी कहा कि अगर कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो उसके लिए नियम है। आप इसके लिए नोटिस दे सकते हैं लेकिन संसद में हंगामा करना और कामकाज में बाधा डालना ठीक नहीं है। सभी ने इसे भी स्वीकार किया है। यह अच्छी बात है कि सभी ने स्वीकार किया है कि कल से चर्चा होगी। हम कल लोकसभा में चर्चा के बाद पहला विधेयक पारित करेंगे। राज्यसभा में भी सूचीबद्ध कार्य पारित किए जाएंगे। मैं एक बार फिर सभी विपक्षी सांसदों और नेताओं से अपील करता हूँ कि आज जो भी समझौता हुए है, उसे कायम रखें। हमें संसद को सुचारु रूप से चलाना चाहिए। कल से संसद सुचारु रूप से चलेगी। ऐसा समझौता हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा।

गतिरोध खत्म करने के साथ संविधान पर बहस की सहमति बन

भाजपा पर्यवेक्षकों के नाम का एलान, सीतारमण-रूपाणी की मौजूदगी में चुना जाएगा महाराष्ट्र का सीएम

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। रांची

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का एलान कर दिया है। पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में यह घोषणा की गई। इनकी मौजूदगी में ही पार्टी विधायक दल के नेता का चयन होगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि वह ही महाराष्ट्र का अगला



मुख्यमंत्री होगा। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक

महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन नहीं हो पाया

चुनावी नतीजों की घोषणा के एक सप्ताह से अधिक समय बाद भी महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भाजपा के फैसले का समर्थन करेंगे। उनकी इस घोषणा के बाद लगभग यह स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होगा।

बयान में कहा गया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सूत्रों के मुताबिक, जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उनका राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो जाएगा। हालांकि, इसे लेकर भाजपा ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं।

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। पटना

बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के 4500 पदों पर ली जा रही परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एक साथ 12 सेंटर पर छापेमारी की। जांच के बाद जो मामले सामने आए, वह हैरान करने वाले थे। सॉल्वर गैंग इस परीक्षा में गड़बड़ी कर रहे थे। इसमें सेंटर संचालकों की भी मिलीभगत थी। ईओयू ने गड़बड़ी करने के आरोप में शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के लोगों, ऑनलाइन परीक्षा



केंद्रों के प्रमुखों, ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के आईटी प्रबंधकों, परीक्षा समन्वयकों और आईटी सहायक कर्मचारियों सहित

किया गया। तीन ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान, यह पाया गया कि प्रॉक्सि सर्वर, रिमोट व्यूइंग एप्लिकेशन और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, एक सॉल्वर गिरोह को वास्तविक समय में ऑनलाइन आधारित परीक्षा तक अनधिकृत पहुंच प्रदान की गई थी। बता दें कि पूरे बिहार में ग्राह के 4500 पदों पर बहाली होनी थी। पटना में 12 सेंटरों पर छापेमारी के दौरान संदिग्धों के पास से व्हाट्सएप चैट, ईमेल, ऑडियो मिले हैं। इसमें परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मिले। इसके बाद परीक्षा रद्द की गई।

गाजियाबाद के अधिवक्ताओं का आंदोलन हुआ तेज



फर्जी मुकदमों के खिलाफ गिरफ्तारी देने पहुंचे वकील

जन एक्सप्रेस। गाजियाबाद

गाजियाबाद जिला जज कोर्ट में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन के बीच गाजियाबाद में वकीलों ने कार्य बहिष्कार करके पहले न्यायालय परिसर पर इकट्ठा हुए और एक साथ दोपहर

चल रही है। बार एसोसिएशन के सचिव अमित नेहरा के अनुसार वकीलों के आंदोलन के दौरान अधिवक्ताओं को डराने के उद्देश्य से फर्जी मुकदमे करवाया जा रहा है। श्री नेहरा ने कहा कि शुक्रवार को ही कविनगर थाना क्षेत्र में 44 नाजद और 80 अज्ञात अधिवक्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। जिसका गाजियाबाद बार एसोसिएशन विरोध करती है। वकील 1 महीने से ज्यादा अपने मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जबतक लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के निलंबन और जिला जज अनिल कुमार नहीं हटाए जाते अथवा निलंबित नहीं किए जाते तबतक अधिवक्ताओं का आंदोलन चलता रहेगा। गाजियाबाद में वकीलों ने रजिस्ट्री, टेक्स और न्यायालय तीनो जगह के अधिवक्ताओं को साथ लेकर मार्च करते हुए कविनगर थाने पर कुच कर दिया और प्रशासन को गिरफ्तार करने की चुनौती दे दिया।

बाद कविनगर थाने पर पहुंचकर गिरफ्तारी देने का एलान किया। जातव्य हो कि एक मुकदमे के दौरान वरिष्ठ वकीलों और जिला जज की आपसी कहासुनी 29 अक्टूबर को किसी मामले की सुनवाई के दौरान हो गई थी। जिसके बाद लगातार आक्रोश बढ़ने पर सूचना के बाद पहुंची पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जिसके बाद से ही पूरे जनपद सहित प्रदेश के वकीलों की हड़ताल क्रमबद्ध तरीके से

डाकघरों पर ‘नटवरलाल’ का साया, पहले बंद पड़े 606 जमा खाते चालू किए, फिर कर दिए बंद, 18.60 करोड़ का गबन

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जेलन कार्यालय ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है, जिसमें आरोपी सब पोस्टमास्टर्स ने

निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर सरकारी राशि के दुरुपयोग की साजिश रची। खास बात है कि यहां पर नटवरलाल की भूमिका सरकार डाकघरों के अधिकारियों ने निभाई। आरोपियों ने पहले डाक विभाग में

बंद पड़े 606 आबतों जमा खातों की लिस्ट निकाली। उन्हें दोबारा से चालू किया। कुछ समय बाद उन्हें फिर से बंद कर दिया। इस जालसाजी के खेल में 18.60 करोड़ रुपये का गबन हो गया।

दर देगा इससे प्रयाश का कितना बड़ा नुकसान होगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों पर निकले सर प्लस 33122 करोड़ सरकारी सब्सिडी किसने की, फ्री बिजली सर प्लस के एवज में अगले 5 वर्षों तक बिजली दरों में कोई बढोतरी नहीं होने देने से बिजली कंपनियों पर रुपया 65909 करोड़ जो बिजली बिल का बकाया है उसे निजी कंपनी क्या वसूल करवायेंगे? श्री लेमां ने कहा कि टॉरेंट पावर जो आज के 14 साल पहले सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में फेंचाइजी के रूप में दिया गया था टॉरेंट पावर ने उसे समय का बिजली बकाया 2200 करोड़ वसूल कर

पावर कारपोरेशन को एप्रोमेंट की शर्तों के तहत क्यों नहीं दिया क्या इस पर कोई देगा जवाब। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने दक्षिणांचल पूर्वांचल के निजीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा उत्तर प्रदेश सरकार को फ्री बिजली घराने को सब्सिडी देगी एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से पावर कारपोरेशन को उपभोक्ताओं से 24947 करोड़ बकाया लेना है और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में पावर कारपोरेशन को 40962 करोड़ लेना है यानी कुल रुपया 65909 करोड़ उपभोक्ताओं से वसूलकर व पावर कारपोरेशन को वापस करेगा और यदि वापस करेगा तो टॉरेंट पावर को जब पावर कारपोरेशन ने फेंचाइजी के रूप में

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हालिया रिपोर्टों के अनुसार, 2023 में ऋण वसूली के दबाव से जुड़े आत्महत्या के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जिसमें लगभग 18 प्रतिशत तक की वृद्धि की बात सामने आई है। जनवरी से नवंबर 2023 तक ढ़ेरो मामले से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जहां लोग

कारण, लगभग 40ब लोग मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे हैं। कुछ तो अवैध वसूली तक का शिकार ऐसी संस्थानों अथवा निजी कंपनियों के कर्मियों के हो जाते हैं। जो डर किसी सेवा देने वाली और गौर वितीय संस्थानों सहित। उनके संरक्षण में चलने वाली निजी कंपनियों के दबाव वाली रिकवरी में तरीकों के

बहुत सा सावर्जनिक स्थान पर आयोजन करें उपभोक्ता परिषद सिद्ध कर देगा कि निजीकरण उपभोक्ताओं के हित में नहीं है और उपभोक्ता परिषद पावर कारपोरेशन के लिए डिस्काम सुधार योजना देने को तैयार है अनेकों ऐसे सवाल हैं। जिनका उत्तर प्रदेश सरकार व पावर कॉरपोरेशन को जवाब देना चाहिए उपभोक्ता परिषद पावर कारपोरेशन को खुली बहस की चुनौती देता है और मैं चाहूंगा कि सरकार एक निष्पक्ष हाई लेवल कमेटी बनाये और उसके सामने पावर कॉरपोरेशन और उपभोक्ता परिषद की

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली प्रबंधन और सरकार को दी खुली चुनौती

- विद्युत वितरण कंपनियों के क्षेत्र को बताया साजिश
- अधिकारियों से मांगा जवाब , नीयत में खोट नहीं तो जवाब दो

जन एक्सप्रेस। गाजियाबाद

पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को लेकर बिजली कर्मचारियों सहित बिजली कर्मचारी संगठन अपनी रणनीति बनाने में जुट गये हैं। जबकि पाँवर कारपोरेशन प्रबंधन जनपदों के जिला अधिकारियों, पुलिस प्रमुखों सहित अन्य विभागों के प्रमुखों को हड़ताल की संध्वनाऊसे निबटने के



प्रयास शुरू करने के निर्देश जारी का दिये है। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन को बहस की चुनौती देते हुए सार्वजनिक स्थान पर एक स्वतंत्र हाई

लेबिल कमेटी के सामने दोनों की सरकार कार लेने की बात कही है। उपभोक्ता परिषद की माने तो वह यह सिद्ध कर देगा निजीकरण उपभोक्ता विरोधी है। जबकि हर पहलू पर सिद्ध

कर देगा इससे प्रयाश का कितना बड़ा नुकसान होगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों पर निकले सर प्लस 33122 करोड़ सरकारी सब्सिडी किसने की, फ्री बिजली सर प्लस के एवज में अगले 5 वर्षों तक बिजली दरों में कोई बढोतरी नहीं होने देने से बिजली कंपनियों पर रुपया 65909 करोड़ जो बिजली बिल का बकाया है उसे निजी कंपनी क्या वसूल करवायेंगे? श्री लेमां ने कहा कि टॉरेंट पावर जो आज के 14 साल पहले सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में फेंचाइजी के रूप में दिया गया था टॉरेंट पावर ने उसे समय का बिजली बकाया 2200 करोड़ वसूल कर

पावर कारपोरेशन को एप्रोमेंट की शर्तों के तहत क्यों नहीं दिया क्या इस पर कोई देगा जवाब। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने दक्षिणांचल पूर्वांचल के निजीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा उत्तर प्रदेश सरकार को फ्री बिजली घराने को सब्सिडी देगी एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से पावर कारपोरेशन को उपभोक्ताओं से 24947 करोड़ बकाया लेना है और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में पावर कारपोरेशन को 40962 करोड़ लेना है यानी कुल रुपया 65909 करोड़ उपभोक्ताओं से वसूलकर व पावर कारपोरेशन को वापस करेगा और यदि वापस करेगा तो टॉरेंट पावर को जब पावर कारपोरेशन ने फेंचाइजी के रूप में

दूसरा क्या निजी घराने किसानों को फ्री बिजली का लाभ देगे और यदि देगे तो नोएडा पावर कंपनी किसानों को फ्री बिजली का लाभ क्यों नहीं दे रही है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसी निजी घराने को सब्सिडी देगी एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से पावर कारपोरेशन को उपभोक्ताओं से 24947 करोड़ बकाया लेना है और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में पावर कारपोरेशन को 40962 करोड़ लेना है यानी कुल रुपया 65909 करोड़ उपभोक्ताओं से वसूलकर व पावर कारपोरेशन को वापस करेगा और यदि वापस करेगा तो टॉरेंट पावर को जब पावर कारपोरेशन ने फेंचाइजी के रूप में

दिया तो आज तक लगभग 2200 करोड़ रूपया टॉरेंट ने वसूल कर पावर कारपोरेशन को वापस क्यों नहीं दिया। निजी घराने आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में सरप्लस के एवज में अगले 5 वर्षों तक बिजली दरों में कोई भी बढोतरी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा अनेकों ऐसे सवाल हैं। जिनका उत्तर प्रदेश सरकार व पावर कॉरपोरेशन को जवाब देना चाहिए उपभोक्ता परिषद पावर कारपोरेशन को खुली बहस की चुनौती देता है और मैं चाहूंगा कि सरकार एक निष्पक्ष हाई लेवल कमेटी बनाये और उसके सामने पावर कॉरपोरेशन और उपभोक्ता परिषद की

बहुत सा सावर्जनिक स्थान पर आयोजन करें उपभोक्ता परिषद सिद्ध कर देगा कि निजीकरण उपभोक्ताओं के हित में नहीं है और उपभोक्ता परिषद पावर कारपोरेशन के लिए डिस्काम सुधार योजना देने को तैयार है अनेकों ऐसे सवाल हैं। जिनका उत्तर प्रदेश सरकार व पावर कॉरपोरेशन को जवाब देना चाहिए उपभोक्ता परिषद पावर कारपोरेशन को खुली बहस की चुनौती देता है और मैं चाहूंगा कि सरकार एक निष्पक्ष हाई लेवल कमेटी बनाये और उसके सामने पावर कॉरपोरेशन और उपभोक्ता परिषद की